आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 25.05.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
- नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
- उत्तराखंड खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया।
- सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुण्ड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिये खोल दिये जाएंगे।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा।

नीति आयोग बैठक–प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हुए अपने यहां कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें। नई दिल्ली में कल नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने एक राज्यः एक वैश्विक गंतव्य पर जोर देते हुए कहा कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा।

नीति आयोग बैठक–मुख्यमंत्री

नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। एक रिपोर्ट–

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते ड्रेनेज की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके समाधान के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिये विशेष योजना बनाने की मांग की। साथ ही "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" की गाइडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने का अनुरोध किया, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सीमितता को दूर किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली "मां नंदा राजजात यात्रा" और 2027 के "हरिद्वार कुंभ" को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के लिए निर्णायक होंगे, और राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की जीडीपी में जहां प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.3 प्रतिशत है, वहीं इसमें 45 प्रतिशत आबादी शामिल है। इसलिए "हाई वैल्यू एग्रीकल्चर" को बढ़ावा देने के लिए सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट मिशन और सगंध खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय खेलों की सफलता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेट जीरो विजन के अनुरूप ग्रीन गेम्स की थीम पर आधारित आयोजन में ई–वेस्ट से बने 4000 पदक और सौर ऊर्जा से पूरी विद्युत आपूर्ति की गई। इससे लगभग 5000 टन कार्बन उत्सर्जन को रोका गया।

प्रभावी क्रियान्वयन निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की बैठक में दिए गए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर स्पष्ट और व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि ''विकसित भारत 2047'' के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करना होगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाने और उसकी नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए। उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने, पारदर्शिता बनाए रखने और जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प में पूरी निष्ठा से सहभागी है।

प्री समिट संपन्न

विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का तीसरा प्री–समिट बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में संपन्न हुआ। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और हिमालयन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में देश–विदेश से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को अहम बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आयोजकों को बधाई दी और बताया कि मुख्य सम्मेलन नवंबर में उत्तराखंड में आयोजित होगा।

भारत रत्न प्रो. सी.एन.आर. राव और डॉ. इंदुमती राव ने इस सम्मेलन में ऑनलाइन सहभागिता की। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने ''सिलक्यारा फ्रेमवर्क'' नामक एक स्वदेशी आपदा प्रबंधन मॉडल प्रस्तुत किया, जो पूर्व–आपदा वैज्ञानिक तैयारी पर आधारित है।

सम्मेलन में चार प्रमुख सत्र आयोजित किए गए जिनमें तकनीकी नवाचार, सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली, पारंपरिक ज्ञान और महिला नेतृत्व की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

खनन राजस्व

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। यह राज्य के खनन क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है, जो मानते थे कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कीर्तिमान न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित में लिए गए निर्णायक निर्णयों का भी उदाहरण है।

हेमकुण्ड साहिब यात्रा

चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुण्ड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिये खोल दिये जांएगे। यात्रा के लिये सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल पंज प्यारों की अगुवाई में पवित्र निशान साहिब के साथ गोविन्दघाट गुरुद्वारा परिसर से रवाना हुआ। इस जत्थे में लगभग चार हजार श्रद्धालु शामिल हैं, जो कल देर शाम घांघरिया पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद यह जत्था आज सुबह घांघरिया से रवाना हुआ, जो लगभग पूर्वाह्न दस बजे हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। इसके बाद इस वर्ष की पहली अरदास होगी और हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

मौसम

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज तड़के से बारिश हो रही है। इसके चलते गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और बागेश्वर में आज आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले चार से पांच दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में धीरे–धीरे गिरावट आने की उम्मीद है।

प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल का प्रोजेक्ट ''नंदा–सुनंदा'' बेटियों की शिक्षा को पुनर्जीवित करने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम बढ़ा रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 12 लाख रुपये की सहायता से 38 बेटियों की शिक्षा दोबारा शुरू करवाई गई है। हाल ही में 5 और बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला है।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा को फिर से शुरू करने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार बताते हुए अभिभावकों से अपील की कि वे बेटियों की पढ़ाई न रुकने दें, प्रशासन उनका साथ देता रहेगा।

संज्ञान/जवाब तलब

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के विकासखंड बीरोंखाल के सुखई में वाहन दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के शव को अस्पताल प्रशासन द्वारा ई–रिक्शा में बांधकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की अमानवीय घटना का संज्ञान लिया है। सतपाल महाराज ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और नैनीताल के सीएमओ डॉ. हरीश पंत से दूरभाष पर बात कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सी०एम०एस से जवाब तलब किया है।

यूसीसी बैठक

हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में यूसीसी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने बताया कि जिले में यूसीसी पंजीकरण के लिए सोलह हजार एक सौ तैंतीस आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तेरह हजार आठ सौ ग्यारह आवेदन अनुमोदित हो चुके हैं। शेष आठ सौ चौरानब्बे आवेदन लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के प्रत्येक सीएससी केंद्र पर प्रतिदिन कम से कम 10 यूसीसी रजिस्ट्रेशन किए जाएं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी तत्काल विवाह पंजीकरण कराएं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता के बाद ही किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से आगामी बैठक से पहले सभी लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।